



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

178-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2024 (KARTIKA 22, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 13th November, 2024

No. 21-HLA of 2024/59/26499.— The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Amendment) Bill, 2024 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 21-HLA of 2024

THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Amendment) Act, 2024. Short title.

2. In section 23 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023,-

- (i) in sub-section (2), for the words “fifty thousand”, the words “five lakh” shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (3), for the words “ten thousand”, the words “one lakh” shall be substituted.

Amendment of
section 23 of
Central Act 46
of 2023.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, the Central Government has enacted the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), which has come into force from 1st day of July, 2024. Under section 23 (2) of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Court of a Magistrate of First Class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding fifty thousand rupees, or of both, or of community service. Further, under section 23 (3) of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Court of a Magistrate of Second Class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one years, or of fine not exceeding ten thousand rupees, or of both, or of community service. It has been observed that under certain Acts like the Negotiable Instruments Act, 1881, the objective of imposition of fine instead of sentence cannot be achieved due to maximum limit of fine prescribed under sections 23 (2) and 23 (3) of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, as the amount involved in cheque bounce cases may be much higher than the fine, which can be imposed under the above sections. Further, for the violations of traffic rules, fines have been increased under the Motor Vehicles Act. The maximum limits of fines under the aforesaid provisions is also not in commensurate with the sentenced, which can be imposed under the above said provisions. Therefore, it has become necessary to increase the limit of fine prescribed under sections 23 (2) and 23 (3) of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023.

A legislation namely, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (Haryana Amendment), Bill, 2024 to increase the limit of the fine, which can be imposed by the Magistrates of First Class and Second Class under sections 23 (2) and 23 (3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 respectively and for matters connected therewith or incidental thereto, is required.

Hence, this Bill.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 13th November, 2024.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2024 का विधेयक संख्या 21-एच०एल०ए०

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, हरियाणा राज्यार्थ
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- यह अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 में,—
(i) उप-धारा (2) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पाँच लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे: तथा 2023 के केन्द्रीय अधिनियम 46 की धारा 23 का संशोधन।
(ii) उप-धारा (3) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) अधिनियमित किया है, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) के तहत, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन साल से अनधिक अवधि के कारावास या पचास हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(3) के तहत, द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक साल से अनधिक अवधि के कारावास या दस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। यह देखा गया है कि कुछ अधिनियमों के तहत जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, जिसके तहत चेक बाउंस मामलों में शामिल राशि जुर्माने से बहुत अधिक हो सकती है, में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23 (3) के तहत निर्धारित जुर्माने की अधिकतम सीमा के कारण जुर्माना लगाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ाया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत जुर्माने की अधिकतम सीमा भी सजा के अनुरूप नहीं है, जो उपरोक्त प्रावधानों के तहत लगाई जा सकती है। इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23(3) के तहत निर्धारित जुर्माने की सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

एक विधान अर्थात्, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23(2) और 23 (3) के तहत प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जा सकने वाले जुर्माने की सीमा को बढ़ाने और उससे जुड़े या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक है।

इसलिए, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 13 नवम्बर, 2024.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।